



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 364]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 30, 2010/आषाढ़ 9, 1932

No. 364]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 30, 2010/ASADHA 9, 1932

गृह मंत्रालय

(केन्द्र-राज्य प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2010

सा.का.नि. 567(अ).—कैदी सम्प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 (2003 का 49) की धारा 3 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबंध सऊदी अरब-राष्ट्र के लिए लागू होंगे तथा उस देश और भारत के बीच कैदियों के अन्तरण के लिए भारत गणराज्य की सरकार और सऊदी अरब-राष्ट्र के बीच हुई संधि के पाठ को निम्न प्रकार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

दण्डित व्यक्तियों के अन्तरण के संबंध में भारत गणराज्य की सरकार तथा
सऊदी अरब-राष्ट्र के बीच करार

भारत-गणराज्य तथा सऊदी अरब-राष्ट्र (जिन्हें इसमें इसके बाद संविदाकारी देश कहा गया है), विद्यमान संबंधों के समर्थन में, दोनों राष्ट्रों के नागरिकों में से दण्डित व्यक्तियों के अन्तरण में सहायता पहुंचाना चाहते हुए, उनका सामाजिक और मानसिक दृष्टि से पुनर्वास करने के उद्देश्य से तथा उक्त क्षेत्र में सहयोग से होने वाले लाभों को समझते हुए निम्नलिखित के प्रति सहमत हो गए हैं :

अनुच्छेद-1

परिभाषा

इस करार के उपबंधों को लागू किए जाने में निम्नलिखित पदों का आशय जब तक पाठ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो, तब तक यथा नियत होगा;

1. अन्तरणकर्ता देश : वह देश, जिसमें व्यक्ति को दंड दिया गया हो;

2. प्राप्तकर्ता देश : वह देश, जहाँ दण्डित व्यक्ति को अपनी सज़ा काटने अथवा शेष सज़ा काटने के लिए अंतरित किया जाना है;
3. दण्डित व्यक्ति : संविदाकारी देशों में से किसी एक देश में प्रवृत्त कानून के अंतर्गत स्थापित किसी न्यायालय अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय के अनुसरण में किसी आदेश के अन्तर्गत कारावास की सज़ा काट रहा कोई व्यक्ति।
4. दण्ड : अपने दंडाधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए किसी न्यायालय अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया स्वतंत्रता से वंचित रखे जाने से युक्त कोई दंड अथवा कार्रवाई।
5. निर्णय : किसी न्यायालय अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई अंतिम आदेश अथवा निर्णय।

अनुच्छेद 2

सामान्य सिद्धांत

1. इस करार के प्रावधानों के अनुसार कोई संविदाकारी देश, दूसरे देश के नागरिकों के विरुद्ध पारित सज़ा को काटने के लिए दण्डित व्यक्तियों को उनकी राष्ट्रियता वाले देश में अंतरित कर सकता है।
2. प्रत्येक संविदाकारी देश, अपने भू-भाग के अन्दर दूसरे देश के नागरिकों के विरुद्ध पारित सज़ा देने वाले अंतिम एवं प्रवर्तनीय अदालती निर्णयों की सूचना, यथाशीघ्र, दूसरे देश को देगा।

अनुच्छेद 3

केन्द्रीय प्राधिकारी

1. संविदाकारी देशों के संबंध में इस करार के कार्यान्वयन के संबंध में प्रभारी प्राधिकारी निम्नानुसार होंगे :-

- सऊदी अरब राष्ट्र के संबंध में : आन्तरिक मंत्रालय।
- भारत-गणराज्य के संबंध में : गृह-मंत्रालय ।

दोनों संविदाकारी देशों में से किसी भी देश द्वारा अपने सक्षम प्राधिकारियों को परिवर्तित किए जाने की स्थिति में ऐसा देश उसके बारे में सरकारी माध्यमों के ज़रिए दूसरे देश को सूचित करेगा।

2. इस करार के प्रावधानों के कार्यान्वयन के बारे में संविदाकारी देशों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच पत्र-व्यवहार, लिखित रूप में तथा उपर्युक्त दो देशों के सरकारी माध्यमों के ज़रिए किया जाएगा।

अनुच्छेद 4

अंतरण हेतु शर्तें

उपर्युक्त दो संविदाकारी देशों में से किसी भी संविदाकारी देश के दंडित व्यक्ति का अंतरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-

1. ऐसा कृत्य अथवा अनाचरण, जिसके फलस्वरूप अंतरणकर्ता देश में सज़ा दी गई हो, वह प्राप्तकर्ता देश के कानून के तहत भी स्वतंत्रता के वंचन के ज़रिए एक अपराध के रूप में दण्डनीय हो;
2. आवेदन प्रस्तुत किए जाने के समय, दंडित व्यक्ति प्राप्तकर्ता देश का नागरिक हो;
3. निर्णय अंतिम तथा प्रवर्तनीय हो;
4. दण्डित व्यक्ति के खिलाफ अंतरणकर्ता देश में कोई आपराधिक कार्यवाही लम्बित नहीं हो;
5. दोनों संविदाकारी देश अंतरण के अनुरोध से सहमत हों;
6. दण्डित व्यक्ति अंतरित किए जाने के प्रति लिखित रूप में सहमति दे दे। यदि, वह अपनी इच्छा लिखित रूप से अभिव्यक्त करने में असमर्थ हो तो, उसके प्रतिनिधि अथवा उसकी ओर से कार्य करने के हकदार रिश्तेदारों में से किसी एक रिश्तेदार द्वारा भी सहमति दी जा सकेगी;
7. अनुरोध प्रस्तुत करते समय सज़ा की बाकी बची अवधि छह माह से कम नहीं हो। अपवादिक मामलों में, यदि सज़ा की बाकी बची अवधि छह माह से कम हो तो भी

संविदाकारी देश अंतरण के प्रति सहमत हो सकते हैं;

8. जब तक दण्डित व्यक्ति का दिवालियापन स्थापित नहीं हो गया हो, दण्डित व्यक्ति समस्त निजी अथवा सार्वजनिक, दण्डादेशित वित्तीय देनदारियों को चुकाएगा अथवा उसके भुगतान की प्रत्याभूति देगा जैसा कि अंतरणकर्ता देश उचित समझे।

अनुच्छेद 5

अन्तरण का अनुरोध

अन्तरण का अनुरोध निम्नलिखित में से किसी के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है :-

1. अन्तरणकर्ता देश ।
2. प्राप्तकर्ता देश।
3. दण्डित व्यक्ति, उसका प्रतिनिधि अथवा उसकी ओर से कार्य करने के हकदार रिश्तेदार। इस बारे में अनुरोध, दोनों में से किसी भी देश को प्रस्तुत किया जाएगा।

अनुच्छेद 6

सूचना प्रस्तुत करने का दायित्व

अन्तरणकर्ता देश निम्नलिखित सूचना और दस्तावेज़ मुहैया करवाएगा :

1. नाम और राष्ट्रीयता, दण्डित व्यक्ति के जन्म की तारीख और स्थान तथा उसके पासपोर्ट अथवा किसी अन्य निजी पहचान के दस्तावेजों की प्रति सहित प्राप्तकर्ता देश में उसका पता, यदि कोई हो, और जहां तक संभव हो, दण्डित व्यक्ति की अंगुलि-छापें।
2. अपराध की परिस्थितियों, समय और स्थान के संक्षिप्त विवरण सहित कानूनों के अनुसार उसके लक्षणों का वर्णन ।
3. दण्डित व्यक्ति के बारे में चिकित्सा, सामाजिक अथवा कोई अन्य रिपोर्ट।
4. अंतिम एवं प्रवर्तनीय निर्णय की प्रमाणित प्रति।

5. सज़ा की अवधि, उसके आरंभ होने की तारीख और दण्ड की बाकी बची प्रवर्तनीय अवधि तथा व्यतीत किए गए संगत निवारक निरोध की अवधि का विवरण।
6. अंतरण के प्रति दण्डित व्यक्ति अथवा उसके कानूनी प्रतिनिधि की सहमति सहित विवरण।
7. दण्डित व्यक्ति के अंतरण के प्रति सहमति व्यक्त करते हुए अंतरणकर्ता देश की ओर से विवरण।

अनुच्छेद 7

सहमति और सत्यापन

अंतरणकर्ता देश के अनुरोध पर, प्राप्तकर्ता देश निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करेगा :

1. ऐसा सरकारी दस्तावेज़, जो यह सिद्ध करता हो कि दण्डित व्यक्ति प्राप्तकर्ता देश का एक नागरिक है।
2. ऐसे विधानों अथवा कानूनों की एक प्रति, जो यह दर्शाते हों कि वे कृत्य अथवा अनाचरण, जिनके कारण सज़ा हुई है, प्राप्तकर्ता देश में अपराध की कोटि में आते हैं।
3. प्राप्तकर्ता देश की ओर से दण्डित व्यक्ति का अंतरण स्वीकार कर लिए जाने से संबंधित विवरण।

अनुच्छेद 8

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी देशों के सक्षम प्राधिकारी, दण्डित व्यक्ति के अन्तरण के अनुरोध के बारे में अपने द्वारा लिया गया निर्णय उसे सूचित करेंगे। दण्डित व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि उसे अपने अनुरोध की स्थिति से अवगत करवाया जाए।
2. दोनों में से कोई संविदाकारी देश, दूसरे देश से अंतरण के अनुरोध से सम्बद्ध कोई पूरक सूचना अथवा दस्तावेज़ मुहैया करवाने का अनुरोध कर सकता है।

अनुच्छेद 9

वस्तुतः अंतरण और लागत

1. दण्डित व्यक्ति का अन्तरण अनुमोदित हो जाने पर, अंतरणकर्ता देश, उसे संविदाकारी देशों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच हुई सहमति से तय तारीख और स्थान पर प्राप्तकर्ता देश को अंतरित कर देगा।
2. दंडित व्यक्ति को ले जाने पर होने वाला परिवहन-व्यय और अपने भू-भाग में सज़ा के प्रवर्तन के फलस्वरूप होने वाला व्यय, प्राप्तकर्ता देश द्वारा वहन किया जाएगा।

अनुच्छेद 10

दण्ड का सतत प्रवर्तन

दण्डित व्यक्ति का अंतरण किए जाने पर :

1. प्राप्तकर्ता देश, अन्तरणकर्ता देश में न्यायालय अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए फैसले में यथानिर्धारित दण्ड के कानूनी स्वरूप एवं अवधि द्वारा बाध्य होगा।
2. प्राप्तकर्तादेश के सक्षम प्राधिकारी, अपने राष्ट्रीय कानून के तहत यथाअपेक्षित, न्यायालय के आदेश अथवा प्रशासनिक आदेश द्वारा दंड का प्रवर्तन जारी रखेंगे।
3. यदि प्राप्तकर्ता देश के कानूनों में उसी अपराध के लिए अधिकतम सीमा का प्रावधान हो और अन्तरणकर्ता देश द्वारा दिए गए दण्ड की अवधि इस प्रकार की अधिकतम सीमा से अधिक हो तो प्राप्तकर्ता देश अपने कानूनों में किए गए प्रावधान के अनुसार दंड को ऐसी अधिकतम सीमा तक कर देगा।
4. प्राप्तकर्ता देश दण्ड की अवधि को नहीं बढ़ाने अथवा दण्ड के बदले में जुर्माना न लगाने के लिए बाध्य होगा।
5. दण्ड का प्रवर्तन, प्राप्तकर्ता देश केवल जिसे ऐसे प्रवर्तन के संबंध में सभी निर्णय लेने का अधिकार हो, में लागू कानूनों के अनुसार किया जाएगा।

अनुच्छेद 11**क्षमा, राजक्षमा अथवा सज़ा को कम किया जाना**

1. केवल अन्तरणकर्ता देश द्वारा ही दी गई क्षमा, राजक्षमा अथवा उसके द्वारा सज़ा को कम किया जाना दण्डित व्यक्ति पर लागू होगा।
2. अन्तरणकर्ता देश प्राप्तकर्ता देश को अपने भू-भाग में लिया गया ऐसी कोई भी निर्णय शीघ्रता से अधिसूचित करेगा, जिसमें दण्ड अथवा उसके हिस्से के प्रवर्तन को समाप्त कर दिया जाना निहित हो। प्राप्तकर्ता देश के सक्षम प्राधिकारी इन निर्णयों को तत्काल कार्यान्वित करेंगे।

अनुच्छेद 12**फैसले की समीक्षा**

अकेले अन्तरणकर्ता देश को ही निर्णय की समीक्षा करने का न्यायिक एवं विधिक अधिकार होगा।

अनुच्छेद 13**दण्डित व्यक्ति का पुनर्विचारण**

इस करार के प्रावधानों के तहत अन्तरित किसी दण्डित व्यक्ति का प्राप्तकर्ता देश द्वारा ऐसे कृत्यों अथवा चूकों के संबंध में पुनर्विचारण नहीं किया जाए जिनके संबंध में दंडित व्यक्ति को अन्तरणकर्ता देश के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा पहले ही दण्डित किया जा चुका हो।

अनुच्छेद 14**दण्ड के प्रवर्तन के बारे में सूचना**

प्राप्तकर्ता देश, अन्तरणकर्ता देश को निम्नलिखित के बारे में अधिसूचित करेगा :

1. जब दण्ड का प्रवर्तन पूरा हो गया हो, ऐसी अधिसूचना का प्रभाव उस दण्ड का निर्वहन अन्तरणकर्ता देश में किए जाने का होगा।

2. यदि दंडित व्यक्ति हिरासत से भाग जाए, तो प्राप्तकर्ता देश द्वारा उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के संबंध में उठाए गए कदम।
3. दंड के प्रवर्तन से संबंधित कोई अन्य मामला।

अनुच्छेद 15

भाषा

अनुरोध एवं समर्थक दस्तावेज अंग्रेजी में होंगे अथवा (इनके किसी अन्य भाषा में होने पर) साथ अंग्रेजी में अनुवाद भेजा जाएगा।

अनुच्छेद 16

अभिवहन

यदि कोई भी संविदाकार देश, दूसरे संविदाकार देश के भू-भाग के ज़रिए किसी अन्य देश से अपने किसी एक नागरिक को अन्तरित करना चाहे तो ऐसा देश उस देश को इस आशय का एक अनुरोध भेजेगा। दूसरा संविदाकार देश, अपने भू-भाग के ज़रिए अभिवहन को सुकर बनाएगा, यदि ऐसा अभिवहन उसके कानूनों के विरुद्ध नहीं हो।

अनुच्छेद 17

कार्यान्वयन के लिए सहयोग

संविदाकार देशों के सक्षम प्राधिकारी इस करार को लागू करने के सर्वाधिक उपयुक्त तरीके तय करने के लिए परस्पर परामर्श करेंगे। वे ऐसे व्यावहारिक उपायों पर भी सहमति बना सकते हैं जो ऐसे करार का लागू किया जाना सुकर बनाने के लिए आवश्यक हों।

अनुच्छेद 18

विवादों का निपटारा

संविदाकार देश अपने सक्षम प्राधिकारियों के बीच परामर्श के ज़रिए इस करार की व्याख्या अथवा इसके लागू होने के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का निपटारा करेंगे। यदि कोई

समझौता नहीं हो पाए तो विवाद को राजनयिक माध्यमों से निपटाया जाएगा।

अनुच्छेद 19 लागू होने का दायरा

इस करार के प्रभावी होने से पूर्व अथवा इसके बाद उपर्युक्त दो संविदाकार देशों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा दिए गए दण्ड के प्रवर्तन पर यह करार लागू होगा।

अनुच्छेद 20 संशोधन

दो संविदाकार देशों की सहमति से इस करार में संशोधन किया जा सकता है, जो उसी प्रक्रिया का निर्वाह किए जाने के बाद प्रवृत्त होगा जो कि इस करार को प्रवृत्त करने के लिए लागू की गई है।

अनुच्छेद 21

अन्तिम प्रावधान

1. संविदाकार देश इस करार को प्रवृत्त करने के लिए सभी आवश्यक कानूनी और संवैधानिक प्रक्रियाएं पूरी करेंगे। यह करार, ऐसी प्रक्रियाएं पूरी कर लिए जाने के बारे में राजनयिक माध्यमों के जरिए अंतिम सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के बाद प्रवृत्त होगा।
2. यह करार, अनिश्चित अवधि के लिए लागू रहेगा।
3. कोई भी देश दूसरे देश को राजनयिक माध्यम द्वारा लिखित नोटिस देकर इस करार को समाप्त कर सकता है। यह करार, ऐसा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से छः महीने व्यतीत हो जाने के बाद समाप्त हो जाएगा। इससे करार की वैधता के दौरान प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

इसके सभी पाठों के समान रूप से प्रामाणिक होने के नाते, इसे 14 रबिया अलावल, 1431 एच अर्थात् 28 फरवरी, 2010 को रियाध में हिन्दी, अरबी, और अंग्रेजी भाषाओं में दो मूल प्रतियों में, तैयार किया गया है। इस करार के प्रावधानों की व्याख्या में मतभेद होने की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा।

भारत गणराज्य
की ओर से

सऊदी अरब-राष्ट्र
की ओर से

हस्ता0/-

हस्ता0/-

गुलाम नबी आज़ाद
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री

नैफ बिन अब्दुलाज़िआ
द्वितीय उप प्रधान मंत्री
आन्तरिक कार्य मंत्री

[फा. सं. 17011/17/2009-पी आर]
निर्मलजीत सिंह कलसी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**(C S DIVISION)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th June, 2010

G.S.R. 567(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections(1) and (2) of section 3 of the Repatriation of Prisoners Act, 2003 (49 of 2003), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act shall apply to the Kingdom of Saudi Arabia and notifies the text of the agreement entered into between the Government of the Republic of India and the Kingdom of Saudi Arabia for the transfer of prisoners between that country and India as follows, namely :-

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF REPUBLIC OF INDIA AND THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA ON THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS"

The Republic of India and the Kingdom of Saudi Arabia (hereinafter referred to as the Contracting States), in support of existing relationships, desiring to establish cooperation in the transfer of Sentenced Persons from nationals of the two States, for the purpose of rehabilitating them socially and psychologically, and realizing the benefits resulting from cooperation in said field, have agreed on the following:

Article 1**DEFINITIONS**

In application of the provisions of this Agreement, the following terms shall have the meanings as assigned to them, unless the text requires otherwise:

1. **Transferring State:** The State in which the sentence was imposed on the person;

2. **Receiving State:** The state to which the sentenced person is to be transferred for serving his sentence or remainder thereof;
3. **Sentenced Person:** Any person undergoing a sentence of imprisonment under an order pursuant to a judgment passed by a court or a competent authority established under the law for the time being in force in either of the Contracting States;
4. **Sentence:** Any punishment or measure involving deprivation of liberty ordered by a court or a competent authority in the exercise of its criminal jurisdiction;
5. **Judgment:** Any final order or decision rendered by a court or a competent authority.

Article 2

GENERAL PRINCIPLES

1. Either Contracting State may transfer the Sentenced Persons to complete the sentence passed against nationals of the other State in the Country of their nationality in accordance with provisions of this Agreement.
2. Each of the Contracting States shall, as soon as possible, notify the other State of final and enforceable judicial judgments awarding Sentences passed within its territory against nationals of the other State.

Article 3

CENTRAL AUTHORITIES

1. Authorities in charge of the implementation of this Agreement for the Contracting States are:
 - For the Kingdom of Saudi Arabia: Ministry of Interior.
 - For the Republic of India: Ministry of Home Affairs.

In case either Contracting State changes its competent authorities, it shall notify the other State of the same through official channels.

2. Correspondence between the competent authorities of the Contracting States regarding the implementation of provisions of this Agreement shall be in writing and through the official channels of the two countries.

Article 4

CONDITIONS FOR TRANSFER

Transfer of sentenced person of either Contracting State shall be subject to the following conditions:

1. The act or omission for which a sentence is imposed in the Transferring State is also punishable as a crime by way of deprivation of liberty under the legislation of the Receiving State;
2. The Sentenced Person is a national of the Receiving State, at the time of submitting the request;
3. The judgment is final and enforceable;
4. No Criminal Proceedings are pending against the Sentenced Person in the Transferring State;
5. Both Contracting States consent to the transfer request;
6. The Sentenced Person consents, in writing, to be transferred. In case he is unable to express his willingness in writing, the consent could be given by his representative or one of his relatives entitled to act on his behalf;
7. The term of the remaining sentence shall not be less than six months at the time of submission of the request. Yet, the Contracting States may – as an exception – agree to the transfer if the remaining period of the sentence is less than six months;
8. Unless his insolvency is established, the Sentenced Person shall have paid off all sentenced financial obligations, private or public, or shall guarantee payment thereof as the Transferring State deems fit.

Article 5

TRANSFER REQUEST

Transfer requests may be submitted by any of the following:

1. Transferring State.
2. Receiving State.
3. The Sentenced Person, his representative, or relatives entitled to act on his behalf. The request, in this regard, shall be submitted to either state.

Article 6

OBLIGATION TO FURNISH INFORMATION

The Transferring State shall provide the following information and documents:

1. The name and nationality, date and place of birth of the sentenced person, and his address, if any, in the Receiving State, along with a copy of his passport or any other personal identification documents, and Fingerprints of the Sentenced Person, as possible
2. A brief statement on circumstances, time and venue of the crime as well as its characterization in accordance with its legislations.
3. A medical, social, or any other report on the Sentenced Person.
4. A certified copy of the final and enforceable judgment.
5. A statement of the duration, date of commencement of the sentence and remaining enforceable period of the punishment and the period of relevant preventive detention served.
6. A statement including the consent of the Sentenced Person or his legal representative to the transfer.
7. A statement from the Transferring State agreeing to the transfer of the Sentenced Person.

Article 7

CONSENT AND VERIFICATION

Upon the request of the Transferring State, the Receiving State shall submit the following:

1. An official document establishing that the Sentenced Person is a national of the Receiving State.
2. A copy of its legislations or laws which indicate that the acts or omissions leading to the sentence amounts to a crime at the Receiving State.
3. A statement from the Receiving State accepting the transfer of the Sentenced Person.

Article 8

SHARING OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall inform the Sentenced Person of the decision taken with regard to his transfer request. The Sentenced Person has the right to be informed regarding the status of his request.
2. Either Contracting State may request the other State to provide supplementary information or documents related to the request for transfer.

Article 9

PHYSICAL TRANSFER & COSTS

1. Upon approval of the transfer of the Sentenced Person, the Transferring State shall transfer him to the Receiving State on the date and venue agreed upon by the competent authorities of the Contracting States.
2. The Receiving State shall bear costs of transporting the Sentenced Person, and expenses resulting from the enforcement of the sentence within its territory.

Article 10**CONTINUED ENFORCEMENT OF SENTENCE**

Upon transfer of the Sentenced Person:

1. The Receiving State shall be bound by the legal nature and duration of the sentence as stipulated in the judgment determined by the court or the competent authority in the Transferring State.
2. The Competent authority of the Receiving State shall continue the enforcement of the sentence through a court order or administrative order as maybe required under its national law.
3. If the legislations of the Receiving State provide for maximum limit for the same offence and the term of the sentence rendered by the Transferring State exceeds such maximum limit, the Receiving State shall adapt the sentence to such maximum limit as provided for in its legislations.
4. The Receiving State shall be obliged not to increase the sentence as to its duration or replace the sentence with a fine.
5. The sentence shall be enforced in accordance with the applicable laws of the Receiving State, which shall solely have jurisdiction to take all decisions relating to such enforcement.

Article 11**PARDON, AMNESTY OR COMMUTATION**

1. Pardon, Amnesty or commutation granted only by the Transferring State shall be applicable to the Sentenced Person.
2. The Transferring State shall promptly notify the Receiving State of any decisions taken in its territory which entails terminating the enforcement of the sentence or part thereof. The competent authorities of the Receiving State shall immediately implement these decisions.

Article 12**REVIEW OF JUDGMENT**

The Transferring State shall solely have the judicial and legal jurisdiction for review of the judgment

Article 13**RE-TRIAL OF THE SENTENCED PERSON**

A Sentenced Person transferred under the provisions of this Agreement may not be retried by the Receiving State for acts or omissions for which the Sentenced Person has already been sentenced by the competent authorities of the Transferring State.

Article 14**INFORMATION ON ENFORCEMENT OF SENTENCE**

The Receiving State shall notify the Transferring State of the following:

1. When the enforcement of the sentence has been completed. Such notification shall have the effect of discharging that sentence in the Transferring State.
2. If the Sentenced Person escapes from custody, and the steps taken by the Receiving State to secure his arrest.
3. Any other matter relating to the enforcement of the sentence.

Article 15**LANGUAGE**

The requests and supporting documents shall be in English or shall be accompanied by a translation into English.

Article 16**TRANSIT**

If either of the Contracting States wishes to transfer one of its nationals from a third country through the territory of the other Contracting State, it shall submit a request to this effect to that State. The other Contracting State shall facilitate the transit through its territory if such transit does not conflict with its legislations.

Article 17**COOPERATION FOR IMPLEMENTATION**

The competent authorities of the Contracting States shall conduct consultations to reach the most efficient means for the application of this Agreement. They may also agree on practical measures that may be necessary to facilitate the application of this Agreement.

Article 18**SETTLEMENT OF DISPUTES**

The Contracting States shall settle any dispute that may arise regarding the interpretation or application of this Agreement through consultations between their competent authorities. In case of not reaching an agreement, the dispute shall be settled through diplomatic channels.

Article 19**SCOPE OF APPLICATION**

This Agreement shall be applicable to the enforcement of the sentence issued by the competent authorities of the Two Contracting States before or after this Agreement's entry into effect.

Article 20**AMENDMENTS**

This Agreement may be amended by an agreement of the Contracting States, which shall enter into force following the same procedure as is applicable for the entry into force of this Agreement.

Article 21**FINAL PROVISIONS**

1. The Contracting States shall complete all the necessary legal and constitutional procedures for entry into force of this agreement. It shall enter into force after thirty days from the date of receipt of last communication through Diplomatic Channels regarding the completion of such procedures.
2. This Agreement shall remain in force for an indefinite period.
3. Either State may terminate this Agreement by a written notice submitted through diplomatic channels to the other State. This Agreement shall terminate after the lapse of six months from the date of receipt of such notice. This shall have no effect on requests submitted during the validity of the Agreement.

Done at Riyadh on 14 Rabea Alawal, 1431H, corresponding to February 28, 2010, in two originals in the Hindi, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of difference of interpretation of the provisions of this Agreement, the English text shall prevail.

For the Republic of India

For the Kingdom of Saudi Arabia

Sd/-

Sd/-

Ghulam Nabi Azad
Minister of health &
Family Welfare

Naif bin Abdulazia
Second Deputy Prime Minister
Minister of Interior

[F. No. 17011/17/2009-PR]

NIRMALJEET SINGH KALSI, Jt. Secy.